उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 7 अंक 18 16-30 सितंबर 2024 ₹ 20/-

वक्फ संशोधन विधेयक पर मुस्लिम संगठनों में मतभेद

- भारत को आईएसआईएस और अलकायदा से खतरा
- इजरायल द्वारा हमास और हिजबुल्लाह के शीर्ष नेतृत्व का खात्मा
- मलेशिया में बच्चों के यौन शोषण के आरोप में 355 मौलवी गिरफ्तार
- बांग्लादेश में उमड़ रहा है पाकिस्तान प्रेम

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

वक्फ संशोधन विधेयक पर मुस्लिम संगठनों में मतभेद 04
हिजबुल्लाह प्रमुख की हत्या के खिलाफ देश के अनेक भागों में प्रदर्शन 07
उत्तर प्रदेश में होटलों व ढाबों पर मालिकों का नाम लिखना अनिवार्य 10
भारत को आईएसआईएस और अलकायदा से खतरा 12
वन नेशन, वन इलेक्शन योजना पर उर्दू मीडिया का निशाना 14

विश्व

मलेशिया में बच्चों के यौन शोषण के आरोप में 355 मौलवी गिरफ्तार 17
बांग्लादेश में उमड़ रहा है पाकिस्तान प्रेम 18
पाकिस्तान में शिया-सुन्नी झड़पों में 46 लोगों की मौत 19
अफगानिस्तान में दाढ़ी काटने और जींस पहनने पर प्रतिबंध 20
जाकिर नाइक पाकिस्तान में 21
ईरान द्वारा 40 लाख अफगान नागरिकों को निष्कासित करने का फैसला 22

पश्चिम एशिया

इजरायल द्वारा हमास और हिजबुल्लाह के शीर्ष नेतृत्व का खात्मा 23
हाशिम सफीद्दीन हिजबुल्लाह का नया प्रमुख 25
पेजर और वॉकी-टॉकी में हुए धमाकों से दहला लेबनान 26
अमेरिका द्वारा इजरायल को पौने नौ अरब डॉलर की सहायता 29
इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देशों का मोर्चा 29
माली के सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पर आतंकी हमला 31

सारांश

इजरायल ने इस्लामी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और हमास की कमर तोड़ दी है। उसने इन दोनों संगठनों के शीर्ष नेतृत्व का सफाया कर दिया है। अब स्वयं ईरान भी मैदान में कूद पड़ा है। सच्चाई तो यह है कि ईरान मुस्लिम जगत में अकेला पड़ गया है और अधिकांश मुस्लिम देश उसकी कोई ठोस सहायता नहीं कर रहे हैं। वास्तव में पूरा मुस्लिम जगत शिया-सुन्नी विभाजन के चंगुल में फंस गया है। इजरायल के खिलाफ सिर्फ शिया देश ही सक्रिय हैं। मुस्लिम जगत का नेता होने का दंभ भरने वाला सऊदी अरब भी गुप्त रूप से इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि हिजबुल्लाह प्रमुख सैयद हसन नसरल्लाह की हत्या के खिलाफ भारत के अनेक नगरों में जो विरोध प्रदर्शन हुए उनमें किसी भी सुन्नी संगठन ने हिस्सा नहीं लिया। सबसे खास बात यह है कि इन प्रदर्शनों को सिर्फ शिया अखबारों ने ही प्रमुखता से छापा है। जबकि सुन्नी अखबारों ने इन खबरों की उपेक्षा की है।

मोदी सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार हेतु संसद में जो वक्फ संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है उस पर मुस्लिम संगठनों में तीव्र मतभेद पैदा हो गए हैं। बरेलवी संप्रदाय, जो आमतौर पर सूफियों और दरगाहों को मान्यता देता है, इस विधेयक का समर्थन कर रहा है। जबकि देवबंदी या वहाबी विचारधारा के मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। सरकारी अनुमान के अनुसार मुस्लिम वक्फ संपत्तियों का वर्तमान मूल्य लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये है। कुछ मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि इन वक्फ संपत्तियों का उपयोग आम मुसलमानों के कल्याण के लिए नहीं हो रहा है और उन पर राजनीतिक माफिया काबिज हैं। मोदी सरकार का दावा है कि इस विधेयक के कानून बनने से वक्फ संपत्तियों की आय और खर्च में पारदर्शिता आएगी और उससे होने वाली आय का इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के आर्थिक एवं शैक्षिक विकास के लिए हो सकेगा।

बांग्लादेश में सत्तारूढ़ गिरोह के तार पाकिस्तान और कट्टरपंथी इस्लामी संगठन जमात-ए-इस्लामी से जुड़े हैं। कहा जाता है कि बांग्लादेश में अवामी लीग की शेख हसीना सरकार के खिलाफ जो जनाक्रोश भड़का था उसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अमेरिका की पाकिस्तानी लॉबी का हाथ था। बांग्लादेश की मुक्ति के बाद पहली बार पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी सरकारी आशीर्वाद से मनाई गई। इस समारोह में पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को विशेष रूप से बुलाया गया था। इस समारोह में जिन्ना को बंगाली मुसलमानों का सच्चा हमदर्द बताया गया और कहा गया कि जिन्ना पाकिस्तान के साथ-साथ बांग्लादेश के भी जनक हैं। अगर पाकिस्तान का निर्माण नहीं होता तो बंगाली मुसलमान हमेशा हिंदुओं के गुलाम बने रहते। इसके साथ ही बांग्लादेश में सत्तारूढ़ गुट अब पाकिस्तान के साथ व्यापारिक और सैन्य संबंध बढ़ाने के लिए भी प्रयत्नशील है। बांग्लादेश में चीन और पाकिस्तान का बढ़ता हुआ प्रभाव भारत के लिए नया सिरदर्द बन सकता है।

अब ईरान और अफगानिस्तान के संबंध भी बिगड़ रहे हैं। ईरान सरकार ने 40 लाख अफगान नागरिकों को ईरान से निष्कासित करके अफगानिस्तान भेजने का फैसला किया है। ईरान सरकार का कहना है कि ये अफगान नागरिक तस्करी और अपराध में लिप्त हैं। इसकी वजह से ईरानी प्रशासन के लिए समस्या पैदा हो रही है। अफगान सरकार ने यह आरोप लगाया है कि ईरान सरकार जिन अफगान मूल के नागरिकों को अपने देश से निष्कासित कर रही है उनमें से अधिकांश लोग ईरान में ही पैदा हुए थे और उनके पास ईरानी पासपोर्ट व वीजा भी हैं। अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता अब्दुल गनी काजीजादा ने आरोप लगाया है कि अफगान मूल के नागरिकों को अवैध घुसपैठिया साबित करने के लिए ईरानी अधिकारी उनके पासपोर्ट और वीजा फाड़ देते हैं।

वक्फ संशोधन विधेयक पर मुस्लिम संगठनों में मतभेद

इंकलाब (21 सितंबर) के अनुसार संसद में केंद्र सरकार द्वारा पेश वक्फ संशोधन विधेयक पर विभिन्न मुस्लिम संगठनों में तीव्र मतभेद पैदा हो गए हैं। अधिकांश मुस्लिम संगठन इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। जबकि ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज, ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से संबंधित कुछ संगठनों ने इसका समर्थन किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी ने कहा है कि इन संगठनों का मुसलमानों में कोई जनाधार नहीं है और न ही वे भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे ऐसे लोग हैं, जिन्होंने हमेशा मुस्लिम कौम की पीठ में छुरा घोंपा है। भाजपा यही चाहती है कि मुसलमानों को विभाजित किया जाए। अब यह खेल पिछड़े मुसलमानों, महिलाओं और सूफियों के नाम पर खेला जा रहा है। जबकि इस कानून से सभी को नुकसान पहुंचेगा और मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों व अन्य ऐतिहासिक इमारतों पर सरकारी कब्जे का रास्ता खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि यह संसदीय समिति एक तमाशे के अतिरिक्त कुछ नहीं है।

हमारा समाज (20 सितंबर) के अनुसार ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल और ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज ने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को दिए अपने ज्ञापन में सरकार द्वारा सदन में पेश वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार का मुख्य स्रोत बन गया है और उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। इन वक्फ संपत्तियों से किसी भी आम मुसलमान को कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसे में यह जरूरी है कि मुस्लिम वक्फ को माफिया गिरोह के चंगुल से मुक्त करवाया जाए ताकि उससे होने वाली आय का इस्तेमाल जरूरतमंद मुसलमानों, विधवाओं और अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए हो सके। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख मौलाना उमर अहमद इलियासी ने भी अपने ज्ञापन में सरकार द्वारा प्रस्तुत विधयेक का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वक्फ राजनीतिक दलों की लूटपाट का

साधन बन गया है और सत्तारूढ़ दल के नेता दशकों से उसका अनुचित इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इलियासी ने कहा कि 80 प्रतिशत वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे हैं और उन्हें मुक्त करवाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वक्फ माफियाओं ने मोटी पगड़ी लेकर वक्फ संपत्ति पर बनी करोड़ों रुपये की दुकानों को नाम मात्र के किराए पर अपने चहेतों को दे रखा है और बिना किराए में वृद्धि किए उनके किराएनामे में विस्तार कर दिया जाता है। यही कारण है कि फतेहपुरी मस्जिद की दुकानों पर काबिज किराएदारों ने बाकायदा जेपीसी को ज्ञापन देकर प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने भी जेपीसी को ज्ञापन देकर सरकार द्वारा संसद में पेश वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ पर काबिज माफियाओं को यह डर है कि अगर यह विधेयक संसद से पारित हो गया तो खरबों रुपये की वक्फ संपत्ति उनके चंगुल से निकल जाएगी, जिसकी कमाई पर वे वर्षों से मौज उड़ा रहे हैं। इसी डर से वे इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। चिश्ती ने कहा कि हमने ज्ञापन में इस बात पर जोर दिया गया है कि मुस्लिम वक्फ संपत्ति का इस्तेमाल आम मुसलमानों के कल्याण के लिए होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि वहाबी मुसलमान (जिनमें देवबंदी प्रमुख हैं) इस विधेयक का इसलिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें दरगाहों और मजारों से कोई अकीदत (श्रद्धा) नहीं है। वैसे भी वहाबी-देवबंदी मुसलमान सूफी और बरेलवी विचारधारा के विरोधी हैं। हालांकि, भारत के 80 प्रतिशत मुसलमान दरगाहों, सूफियों और पीर-फकीरों की मजारों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, इसलिए देवबंदी भारतीय मुसलमानों के प्रतिनिधि नहीं हैं। चिश्ती ने दावा किया कि देवबंदियों के तार प्रारंभ से ही कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, इसलिए कांग्रेस उनका समर्थन करती आ रही है।

अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सैयद सरवर चिश्ती ने कहा है कि ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल की ओर से जेपीसी के सामने जो प्रतिनिधिमंडल पेश हुआ है उसका नेतृत्व सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने किया था। उनका अजमेर शरीफ दरगाह से कोई संबंध नहीं है। यह देश के मुसलमानों को गुमराह करने का एक सरकारी प्रयास है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीम अफजल ने कहा है कि सत्तारूढ़ भाजपा हर कीमत पर इस विधेयक को संसद से पारित करवाना चाहती है, क्योंकि उसकी नजर खरबों रुपये की वक्फ संपत्तियों पर है। मोमिन कांफ्रेंस

के प्रमुख शकील उज्जमान अंसारी ने कहा है कि भाजपा पसमांदा मुसलमानों के नाम पर मुसलमानों को विभाजित करना चाहती है ताकि वह देश के मुसलमानों को गुमराह कर सके। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों पर सरकारी कब्जे को आसान बनाना है।

समाचारपत्र के अनुसार जेपीसी की आज की बैठक में काफी गरमा-गरमी हुई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जेपीसी को एक ज्ञापन सौंपा और इस्लाम के अनुसार वक्फ संपत्ति की स्थिति पर प्रकाश डाला। बोर्ड ने कहा कि इस्लामी शरिया के अनुसार वक्फ संपत्ति में किसी भी व्यक्ति को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। बोर्ड ने दावा किया कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।

उर्दू टाइम्स (13 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि वक्फ विशुद्ध रूप से मुसलमानों का मामला है और इस पर गैर-मुसलमानों से राय लेने की कोई जरूरत नहीं है। इससे सरकार की नीयत का पता चलता है। जाहिर है कि सांप्रदायिक तत्वों के इशारे पर देश के गैर-मुसलमान वक्फ के खिलाफ ही अपनी राय देंगे।

मुंबई उर्दू न्यूज (14 सितंबर) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दावा किया है कि वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में तीन करोड़ 50 लाख ज्ञापन जेपीसी को भिजवाए जा चुके हैं।

उर्दू टाइम्स (13 सितंबर) ने अपने संपादकीय में अपील की है कि मुसलमानों को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दावे से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस विधेयक के पक्ष में इससे दोगुने ज्ञापन जेपीसी के पास पहुंच चुके हैं।

उर्दू टाइम्स (12 सितंबर) ने अपने संपादकीय में संतोष प्रकट किया है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उनकी पार्टी सरकार को किसी भी धार्मिक संपत्ति को हड़पने की अनुमति नहीं देगी और शिवसेना इसका डटकर विरोध करेगी।

हिंदुस्तान (2 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तानाशाही तरीके अपनाने का आरोप लगाया है। समाचारपत्र ने कहा है कि अमित शाह ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यह धमकी दी है कि वक्फ संशोधन विधेयक को संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा और इसका विरोध करने वालों को 'सीधा' कर दिया जाएगा। समाचारपत्र ने कहा है कि मुसलमान और विपक्षी दल इस विधेयक का इसलिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकार इस कानून के जरिए इस्लाम में हस्तक्षेप करके मुसलमानों की अलग पहचान को खत्म करना चाहती है। यह देश के संविधान और सेक्युलरिज्म के सरासर खिलाफ है।

एतेमाद (28 सितंबर) के अनुसार अहमदाबाद में आयोजित जेपीसी की बैठक में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी के बीच गरमा-गरम बहस हुई। ओवैसी ने कहा कि मुसलमान वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ हैं, इसलिए इसे वापस लिया जाना

चाहिए। इस पर जेपीसी के अध्यक्ष जगदंपिका पाल ने कहा कि इसके लिए आपने अभियान शुरू कर रखा है। ओवैसी ने कहा कि यह विधेयक इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम आखिरी दम तक इसका विरोध करते रहेंगे। यह मुसलमानों के मूलभूत अधिकारों को छीनने का प्रयास है।

उर्दू टाइम्स (9 सितंबर) के अनुसार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिया है कि हम वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में किसी भी कीमत पर पारित नहीं होने देंगे और इसका डटकर विरोध करेंगे।

उर्दू टाइम्स (17 सितंबर) के अनुसार जेपीसी को इस विधेयक के खिलाफ छह करोड़ से अधिक ईमेल भेजे जा चुके हैं। दूसरी ओर, एबीपी न्यूज ने दावा किया है कि कमेटी के पास सिर्फ 84 लाख सुझाव आए हैं। इसके अतिरिक्त लिखित सुझावों से भरे हुए 70 बॉक्स भी कमेटी के पास आए हैं। समाचारपत्र ने पूछा है कि क्या इस विधेयक के खिलाफ जो ज्ञापन भेजे गए थे उनमें हेराफेरी की जा रही है? इस संबंध में मुस्लिम संस्थानों को सतर्क रहने की जरूरत है।

मुंबई उर्दू न्यूज (25 सितंबर) ने देश के मुसलमानों को मशवरा दिया है कि वे वक्फ मामले को सड़क पर लेकर न जाएं, क्योंकि अगर वे ऐसा करेंगे तो मुस्लिम विरोधी सांप्रदायिक पार्टियां उनके आंदोलन का गलत इस्तेमाल करके देश के बहुसंख्यक समाज में मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करने का प्रयास करेंगी।

उर्दू टाइम्स (17 सितंबर) ने अपने संपादकीय में मुसलमानों से अपील की है कि वे भाजपा के सांप्रदायिक जाल में न फंसें।

हिजबुल्लाह प्रमुख की हत्या के खिलाफ देश के अनेक भागों में प्रदर्शन

अवधनामा (30 सितंबर) के अनुसार आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख सैयद हसन नसरल्लाह की इजरायल द्वारा हत्या किए जाने के खिलाफ मुसलमानों ने भारत के अनेक नगरों में उग्र प्रदर्शन किए हैं। नसरल्लाह के लेबनान में मारे जाने की खबर मिलते ही 10 हजार से अधिक मुसलमान लखनऊ स्थित छोटा इमामबाड़ा पहुंचे और उन्होंने बड़ा इमामबाड़ा तक उग्र प्रदर्शन किया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। उनके हाथों में हिजबुल्लाह के झंडे और नसरल्लाह के चित्र थे। प्रदर्शनकारी काले कपड़े पहनकर मातम मना रहे थे और इजरायल व अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे थे। प्रदर्शन के अंत में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के नेताओं के पुतले भी जलाए गए।

रोजनामा सहारा (30 सितंबर) के अनुसार लखनऊ के एक दर्जन से अधिक स्थानों पर हसन नसरल्लाह की मौत पर मातम का आयोजन किया गया और नगर के विभिन्न भागों में कैंडल मार्च निकाला गया। इस मार्च में अमेरिका-इजरायल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस संबंध में दरगाह हजरत अब्बास, रुस्तम नगर में एक शोकसभा का भी आयोजन किया गया। इस सभा को संबोधित करते हुए शिया नेता मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी ने कहा कि "इस्लाम में शहीद से ऊपर कोई दर्जा नहीं होता। हसन नसरल्लाह इस्लाम और रसूल के लिए शहीद हुए हैं। हम दबने वाले नहीं हैं। अगर इजरायल एक नसरल्लाह को शहीद करता है तो हजारों नसरल्लाह उसकी जगह लेंगे। मुसलमान इजरायल और अमेरिका के खिलाफ

अपने खून के आखिरी कतरे तक संघर्ष करते रहेंगे। जो मीडिया हसन नसरल्लाह और हिजबुल्लाह को आतंकवादी कहता है, वह इजरायल के धन पर पल रहा है। असली आतंकवादी नसरल्लाह नहीं, बल्कि नेतन्याहू है।" ऐसी ही एक सभा का आयोजन मस्जिद राहते सुल्तान नूरबाड़ी में भी किया गया। इस सभा को मौलाना सोहेल रिजवी ने संबोधित किया। नसरल्लाह की हत्या के गम में शियाओं ने लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अनेक भागों में अपने इमामबाड़ों, कर्बलाओं और दरगाहों पर काले झंडे लगाए।

इंकलाब (1 अक्टूबर) के अनुसार हसन नसरल्लाह की हत्या के विरोध में देश के अनेक भागों में इजरायल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। श्रीनगर में आयोजित एक प्रदर्शन में पांच हजार से अधिक लोग शामिल हुए, जिसमें भारी संख्या में बुर्कापोश महिलाएं भी शामिल थीं। प्रदर्शनकारियों को 'दुख्तरान-ए-मिल्लत' की महिलाओं ने संबोधित किया। प्रदर्शनकारी अपने हाथों में काले झंडे और नसरल्लाह के चित्र लिए हुए थे। बडगाम, बांदीपुरा और बारामूला जिले के कई इलाकों में नसरल्लाह की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया गया। श्रीनगर के आलमगिरी बाजार में भी प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। नसरल्लाह की हत्या के विरोध में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती ने अपना चुनावी अभियान एक दिन के लिए स्थगित कर दिया और उन्होंने राज्यभर में हड़ताल का आयोजन करने की भी अपील की। नेशनल कांफ्रेंस के नेता और लोकसभा सांसद आगा रुहुल्लाह मेहदी की अपील पर लद्दाख के अनेक भागों में शोकसभा का आयोजन किया गया और इजरायल व अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किए गए। छत्तीसगढ़ के रायपुर और चंदेरी में भी हड़ताल का आयोजन किया गया और उग्र प्रदर्शन किया गया। कोलकाता और असम के अनेक भागों में मुसलमानों द्वारा उग्र प्रदर्शन किए जाने के समाचार मिले हैं। हैदराबाद में भी इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन किए गए।

देश से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी उर्दू अखबारों ने अपने संपादकीय में हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह को श्रद्धांजलि अर्पित की है और अमेरिका व इजरायल की निंदा की है।

अवधनामा (29 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इजरायल ने यह साबित कर दिया है कि उसकी नजर में संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद की कोई कद्र नहीं है और न ही वह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को कोई महत्व देने के लिए तैयार है। विश्व की शक्तियां गाजा में मासूम

फिलिस्तीनियों के नरसंहार को रोकने में विफल रही हैं। इजरायल ने हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह के साथ-साथ उसके अनेक महत्त्वपूर्ण कमांडरों की भी हत्या कर दी है। इससे पहले वह हमास के प्रमुख इस्माइल हानियेह की भी हत्या कर चुका है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने विश्वभर के मुसलमानों से अपील की है कि वे इजरायल के खिलाफ एकजुट हों। उन्होंने कहा कि "इस्लाम के मुजाहिदीन का यह इतिहास रहा है कि वे इस्लाम दुश्मन ताकतों के खिलाफ अपने सिर पर कफन बांधकर मैदान में उतरते हैं और अपने दुश्मनों का सफाया करके ही दम लेते हैं। हसन नसरल्लाह की हत्या पूरे मुस्लिम जगत के लिए सदमा है। इस्लाम और रसूल की रक्षा के लिए सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होकर इजरायल और अमेरिका के खिलाफ निर्णायक युद्ध छेड़ देना चाहिए।"

उर्दू टाइम्स (27 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इजरायल ने गाजा के बाद अब लेबनान को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अफसोस की बात यह है कि मुस्लिम देश इजरायल के खिलाफ एकजुट होकर कोई निर्णायक कदम उठाने में अभी तक विफल रहे हैं। इससे इजरायल की आक्रामक गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है।

उर्दू टाइम्स (29 सितंबर) ने अपने संपादकीय में नसरल्लाह की हत्या पर शोक प्रकट किया है और कहा है कि इजरायल इससे पहले हमास प्रमुख हानियेह को भी अपना निशाना बना चुका है। यह किसी एक देश की क्षति नहीं, बल्कि पूरे इस्लामी जगत की क्षति है। सवाल यह है कि क्या मुस्लिम देश इजरायल के खिलाफ संयुक्त रूप से कोई निर्णायक कदम उठाएंगे या सिर्फ निंदा करते रहेंगे? समाचारपत्र ने अपील की है कि इजरायल के जुल्म का सामना करने के लिए दुनियाभर के मुसलमानों को एकजुट होकर मैदान में आ जाना चाहिए और इस्लाम के दुश्मनों को बर्बाद करने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहिए।

हिंदुस्तान (30 सितंबर) ने कहा है कि नसरल्लाह की हत्या के बाद ईरान ने इजरायल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। अब इजरायल के खिलाफ ईरान के साथ-साथ इराक और सीरिया में भी मोर्चा खोल दिया गया है। इजरायल जिस तरह से हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को नेस्तनाबूद करने में जुटा हुआ है उसे देखते हुए ईरान के पास पलटवार करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं था। सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या अकेले ईरान इजरायल और अमेरिका का मुकाबला कर पाएगा? क्या 100 से अधिक मुस्लिम देश मूकदर्शक बनकर मुसलमानों का नरसंहार देखते रहेंगे या इजरायल व अमेरिका के इस्लाम विरोधी मंसूबों को धूल में मिलाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे? खेद की बात यह है कि अभी तक अनेक मुस्लिम देश मुसलमानों के नरसंहार को मूकदर्शक बनकर देख रहे हैं।

अखबार-ए-मशरिक (30 सितंबर) ने अपने संपादकीय में खेद प्रकट किया है कि यूरोपीय देशों में अगर कुत्ता भी मर जाता है तो पश्चिमी देश आसमान सिर पर उठा लेते हैं, लेकिन इजरायल पिछले एक साल से मुसलमानों के खून की होली खेल रहा है और मानवाधिकारों

के कथित रक्षक मूकदर्शक बनकर हजारों मासूम लोगों के कत्लेआम को देख रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश खुलकर इजरायल का समर्थन कर रहे हैं उसे देखते हुए इसकी कोई संभावना नजर नहीं आती कि खून की यह होली कभी रूक सकेगी।

उत्तर प्रदेश में होटलों व ढाबों पर मालिकों का नाम लिखना अनिवार्य

इंकलाब (25 सितंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से खाद्य पदार्थों से संबंधित सभी दुकानों, ढाबों, होटलों और रेस्टोरेंटों पर मालिकों का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। यह फैसला उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की एक बैठक में लिया गया है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें यह शिकायतें मिली हैं कि खाद्य पदार्थों में हानिकारक सामग्री मिलाई जा रही हैं। स्वास्थ्य नियमों को लागू करने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है कि चाहे वे खाना बनाने वाले हों या उसे परोसने वाले सभी को मास्क और दस्ताने पहनने होंगे। इसके साथ ही दुकानदारों को सीसीटीवी कैमरे भी लगाने होंगे और उसकी फुटेज को सुरक्षित रखना होगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस और प्रशासकीय अधिकारी उनका निरीक्षण कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य पदार्थ बनाने या परोसने वाले सभी दुकानों व ढाबों की संपूर्ण रूप से जांच करवाई जाएगी और उसके कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन करवाया जाएगा। जरूरत पड़ी तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में भी संशोधन किया जाएगा। जो लोग खाद्य सामग्रियों में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थ मिलाते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ियों के मार्ग पर खाद्य सामग्री बेचने वालों को नेम प्लेट लगाने का निर्देश दिया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद रद्द कर दिया गया था।

इंकलाब (26 सितंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे कुछ विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया

है कि सरकार इस तरह के आदेश देकर दलितों और मुसलमानों के रोजगार को ठप करने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी का कहना है कि राज्य सरकार का यह फैसला राजनीति से प्रेरित है, इसलिए इसका विरोध किया जाना चाहिए। इसी पार्टी के एक अन्य नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा है कि अब पुलिस फर्जी मुकदमे का डर दिखाकर राज्य के सभी दुकानदारों से रिश्वत वसूल करेगी। कांग्रेस नेता अरशद आजमी ने भी इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को बीफ फैक्ट्री चलाने वालों के नाम भी उजागर करने का आदेश देना चाहिए।

रोजनामा सहारा (28 सितंबर) के अनुसार फतेहपुरी मस्जिद के इमाम मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम अहमद ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले की निंदा करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री योगी मुसलमानों के खिलाफ झूठे आरोप जानबूझकर लगा रहे हैं और राज्य में मुस्लिम विरोधी माहौल पैदा कर रहे हैं। जमीयत उलेमा ने भी इस फैसले की निंदा करते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। जमात-ए-इस्लामी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से राज्य में सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत ने भी योगी सरकार पर राज्य में सांप्रदायिक नफरत फैलाने का आरोप लगाया है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (25 सितंबर) ने अपने संपादकीय में योगी सरकार के इस फरमान की आलोचना की है। समाचारपत्र ने कहा है कि अब देश के सबसे बड़े राज्य में चलने वाले होटलों के मालिकों के नाम उजागर करना अनिवार्य बना दिया गया है। इस फैसले का उद्देश्य सांप्रदायिकता को हवा देना है। समाचारपत्र ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी तरह का फैसला कांवड़ यात्रा के दौरान भी किया था, जिसका अनुसरण कुछ अन्य राज्य सरकारों ने भी किया था। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी। समाचारपत्र ने कहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि खाद्य पदार्थों की स्वच्छता का ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन इस बहाने धर्म या मजहब पर आधारित राजनीतिक खेल खेलना निंदनीय है। राज्य सरकार के इस फैसले का लाभ होटलों और ढाबों के सिर्फ अमीर मालिकों को ही होगा। जबकि रेहड़ियों पर खाद्य पदार्थ बेचने वाले पुलिस के उत्पीड़न का शिकार बनेंगे और इससे भ्रष्टाचार का नया युग शुरू होगा।

मुंबई उर्दू न्यूज (25 सितंबर) ने अपने संपादकीय में योगी सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। समाचारपत्र ने कहा है कि इससे राज्य में सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिलेगा और हिंदू-मुस्लिम तनाव में बढ़ोतरी होगी। ऐसे कानून आम तौर पर राजनीतिक लाभ उठाने के लिए बनाए जाते हैं। हालांकि, सरकार ने यह दावा किया है कि यह फैसला उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जबकि कुछ अन्य लोगों का आरोप है कि यह फैसला एक वर्ग को सामाजिक बहिष्कार का निशाना बनाने के लिए किया गया है।

हिंदुस्तान (28 सितंबर) ने कहा है कि वैसे तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन फिर भी वहां पर रहने वाले मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। पहले एक कांग्रेसी मंत्री अनिरुद्ध सिंह के इशारे पर मस्जिदों को निशाना बनाया गया था। अब एक अन्य मंत्री विक्रमादित्य

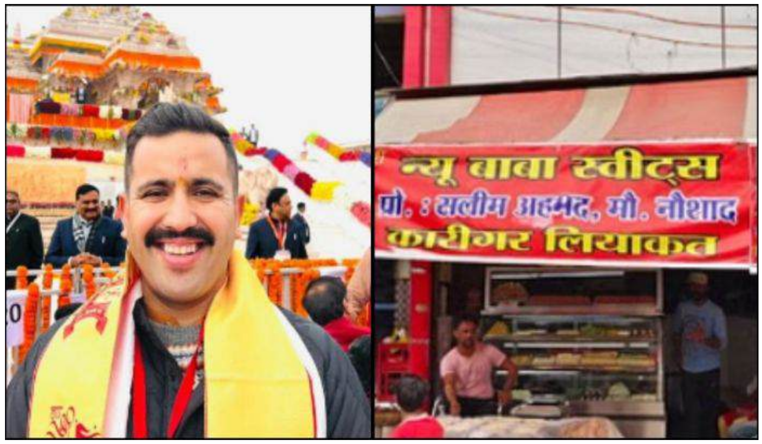

सिंह के मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का अनुसरण करते हुए एक फरमान जारी किया है। इस फरमान के अनुसार राज्य के सभी दुकानों, होटलों और ढाबों पर उनके मालिकों का नेम प्लेट लगाना होगा। इसका मतलब यह है कि अब एक विशेष वर्ग का आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। हालांकि, हिमाचल प्रदेश के कांग्रेसी मंत्री ने यह तर्क दिया है कि यह कदम खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने और जनता को उच्चकोटि का खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए किया गया है।

समाचारपत्र ने कहा है कि कुछ लोगों की शिकायत का संज्ञान लेते हुए जब कांग्रेस हाईकमान ने हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह को दिल्ली तलब किया तो उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी भी नागरिक को कारोबार करने से रोकने का नहीं है और उनके इस फैसले का योगी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। मंत्री का यह स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है। राज्य सरकार का इरादा कुछ और है, जिसकी पर्देदारी की जा रही है। संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी निरंतर हिंदुत्व की ध्वजवाहक सरकार और मुस्लिम दुश्मन भाजपा व संघ परिवार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के लोग उनके इन प्रयासों में पलीता लगा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि कांग्रेस हाईकमान राज्य सरकार पर दबाव डाले ताकि वह मुस्लिम विरोधी नीति अपनाने से बाज आए।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (27 सितंबर) ने अपने संपादकीय में हिमाचल प्रदेश सरकार की आलोचना की है और कहा है कि उसके एक मंत्री के इस आदेश से कांग्रेस को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस हाईकमान ने सख्त नाराजगी प्रकट की है और इसे वापस लेने का निर्देश दिया है। अजीब बात है कि जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस तरह का फैसला किया था तो कांग्रेस ने उसकी आलोचना की थी, लेकिन अब एक कांग्रेसी मंत्री ही योगी सरकार के इस फैसले को लागू करने पर कटिबद्ध है। ऐसे गैरजिम्मेदार मंत्रियों के फैसलों से कांग्रेस की छवि धूमिल होगी। जरूरत इस बात की है कि राज्य की कांग्रेस सरकार अपने इस फैसले पर रोक लगाए।

भारत को आईएसआईएस और अलकायदा से खतरा

अखबार-ए-मशरिक (20 सितंबर) के अनुसार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने अपनी रिपोर्ट में यह चेतावनी दी है कि इस्लामी आतंकी संगठन आईएसआईएस और अलकायदा भारत में व्यापक पैमाने पर खून की होली खेलने की तैयारी कर रहे हैं। पेरिस स्थित इस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने कहा है कि भारत में सक्रिय आतंकी इस्लामी संगठनों को देश में हिंसा को प्रोत्साहन देने और चुनी हुई सरकार का तख्ता पलटकर शरिया हुकूमत स्थापित करने के लिए

विदेशी स्रोतों से भारी धनराशि प्राप्त हो रही है। इस संगठन ने अपनी रिपोर्ट में यह चिंता प्रकट की है कि भारत में आतंकी गतिविधियों में लिप्त जो गिरोह पकड़े जाते हैं उनमें से अधिकांश लोग ऊपरी अदालतों से छूट जाते हैं, क्योंकि भारतीय जांच एजेंसियां अदालत में उनके खिलाफ ठोस प्रमाण पेश करने में विफल रहती हैं। भारतीय अदालतों में विचाराधीन मुकदमों की संख्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, इसलिए इन आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमो की सुनवाई तीव्र गति से नहीं हो पा रही है। ऐसे में यह जरूरी है कि भारत सरकार अपनी जांच एजेंसियों और उनसे संबंधित कानूनी प्रकोष्ठ का पुनर्गठन करे। बताया जाता है कि यह रिपोर्ट 368 पृष्ठों की है। इस रिपोर्ट में 2010 के बाद भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने में विदेशी धन की भूमिका का विश्लेषण किया गया है।

इंकलाब (30 सितंबर) के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने महाराष्ट्र सरकार को सतर्क किया है कि इस्लामी आतंकवादी आने वाले दिनों में मुंबई में कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। इस चेतावनी के बाद पूरे महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस संबंध में रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों और हवाई अड्डों पर नियुक्त सुरक्षाकर्मियों की संख्या में भारी वृद्धि की गई है। एक अन्य मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस्लामी आतंकी संगठन आईएसआईएस ने राजस्थान के एक दर्जन से अधिक महत्त्वपूर्ण नगरों में विस्फोट करने की धमकी दी है। इस चेतावनी के बाद पूरे राजस्थान में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है।

एतेमाद (25 सितंबर) के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने तमिलनाडु के 11 स्थानों पर एक साथ छापे मारे और प्रतिबंधित संगठन हिज्ब उत-तहरीर से संबंधित कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। गौरतलब है कि तमिलनाडु पुलिस इससे पहले 11 लोगों को इस केस में गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार लोगों के कब्जे से विदेशी मुद्रा और देशद्रोही साहित्य बरामद हुआ है। पकड़े गए लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल उपकरणों के विशेषज्ञ बताए जाते हैं। एनआईए द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रतिबंधित संगठन हिज्ब उत-तहरीर का संबंध इस्लामी आतंकी संगठन अलकायदा और आईएसआईएस से है। यह आतंकी संगठन विदेशी सहायता के बल पर भारतीय मुस्लिम युवकों को आईएसआईएस में भर्ती करता था और उन्हें गुप्त रूप से विदेश भेजा जाता था। वहां पर उन्हें हथियार चलाने और विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। यह संगठन भारत की वर्तमान सरकार का तख्ता पलटकर देश में इस्लामी खिलाफत की स्थापना करने की साजिश रच रहा था।

गौरतलब है कि हिज्ब उत-तहरीर की स्थापना तकी अल-दीन अल-नभानी ने 1953 में की थी। एनआईए ने इस संगठन के सदस्य जलील अजीज अहमद को बेंगलुरु हवाई अड्डे से तब गिरफ्तार किया था जब वह दुबई भागने की कोशिश कर रहा था। उससे पूछताछ के बाद इस गिरोह से संबंधित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें डॉ. हामिद हुसैन, अहमद मंसूर, अब्दुल रहमान, मोहम्मद मौरिस, कादर नवाज शरीफ और अहमद अली उमरी शामिल हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि इस संगठन में भर्ती किए गए मुस्लिम युवकों को हिंसक गतिविधियों का प्रशिक्षण देने के लिए अनेक गुप्त प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन किया गया था।

वन नेशन, वन इलेक्शन योजना पर उर्दू मीडिया का निशाना

रोजनामा सहारा (19 सितंबर) के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनी 'वन नेशन, वन इलेक्शन' कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में एक विधेयक पेश करेगी। इस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार तमाम राज्य विधानसभाओं की अवधि लोकसभा के अगले चुनाव अर्थात् 2029 तक बढ़ा दी जाएगी। त्रिशंकु विधानसभा या अगर किसी सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो

जाता है तो शेष अवधि के लिए उपचुनाव करवाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वन नेशन, वन इलेक्शन से लोकतंत्र को नया जीवन मिलेगा और उसमें जनता की भागीदारी बढ़ेगी। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि यह योजना व्यावहारिक नहीं है। मोदी सरकार यह शोशा मूलभूत समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए छेड़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे चुनावी सुधार की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम बताया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा ने कहा है कि यह नई बात नहीं है। पहले भी इस विचार पर काम हुआ था, लेकिन व्यावहारिक नहीं होने के कारण इसे छोड़ दिया गया था। ऑल इंडिया मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लोकतंत्र विरोधी बताया है। वहीं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यह देश में एक पार्टी की सरकार लाने का प्रयास है।

इसी समाचारपत्र ने अपने संपादकीय में कहा है कि यह कल्पना देश के संघीय ढांचे की अवधारणा के सरासर खिलाफ है और इससे संसदीय लोकतंत्र की कब्र खुद जाएगी। यह देश में तानाशाही स्थापित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इससे लोकतंत्र कमजोर होगा और जनता के अधिकारों का हनन होगा।

उर्दू टाइम्स (20 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इससे सरकार के खतरनाक इरादों का संकेत मिलता है, जो इस देश में तानाशाही स्थापित करने का प्रयास कर रही है। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने से खर्च में कमी होने के बजाय और बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके लिए लाखों अतिरिक्त ईवीएम मशीनों की जरूरत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश का तानाशाह बनने का जो स्वप्न देख रखा है, यह योजना उसी दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

हिंदुस्तान (20 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इस देश के आकार को देखते हुए संसद और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाना व्यावहारिक नहीं है। अभी तक एक राज्य का चुनाव भी अनेक चरणों में करवाया जाता है। जब हम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का चुनाव एक साथ करवाने में सक्षम नहीं हैं तो क्या देश के संसद और सभी राज्यों के विधानसभाओं का चुनाव एक ही दिन में करवाना दिवास्वप्न नहीं है?

एतेमाद (21 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि विपक्ष के तेवर को देखते हुए सरकार की इस योजना को संसद से मंजूरी मिलना संभव नजर नहीं आता है। इससे इंकार नहीं किया

जा सकता कि प्रधानमंत्री मोदी वन नेशन, वन इलेक्शन का ख्वाब देख रहे हैं। इससे पहले 1952 से लेकर 1967 तक सीमित पैमाने पर इसका परीक्षण किया गया था, जो विफल रहा। संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी, जो वर्तमान समय में संभव नजर नहीं आता। अगर यह कल्पना कार्यान्वित हो जाती है तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान क्षेत्रीय दलों को होगा, क्योंकि संसद और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ होने के कारण वे अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को जनता के सामने सही ढंग से पेश नहीं कर पाएंगे। भाजपा का दावा है कि एनडीए में शामिल सभी पार्टियां एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में हैं, इसलिए उसे संविधान संशोधन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। भाजपा को यह याद रखना चाहिए कि अभी संसद में उसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है और वह बैसाखियों पर टिकी हुई हैं। जबकि विपक्ष इस बार ज्यादा मजबूत और सक्रिय है। ऐसे हालात में इसकी कोई संभावना नजर नहीं आती कि भाजपा मनमानी करने में सफल हो पाएगी।

अवधनामा (20 सितंबर) ने कहा है कि सरकार संसद, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ करवाने का जो स्वप्न देख रही है, वह व्यावहारिक नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दल इस योजना का विरोध कर रहे हैं। इससे इस धारणा की पुष्टि होती है कि भाजपा इस देश में तानाशाही स्थापित करना चाहती है। उसका यह मंसूबा है कि पूरा देश उसके चंगुल में फंसा रहे। यह परिकल्पना लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। अगर इस योजना को लागू किया गया तो इससे अनेक तरह के संवैधानिक संकट पैदा होंगे।

सियासत (23 सितंबर) ने अपने संपादकीय में सरकार की इस योजना को अव्यावहारिक और लोकतंत्र विरोधी बताया है। समाचारपत्र ने कहा है कि सरकार इस बहाने विपक्ष का सफाया करना चाहती है और देश में एक ही पार्टी की सरकार को थोपना चाहती है।

मलेशिया में बच्चों के यौन शोषण के आरोप में 355 मौलवी गिरफ्तार

उर्दू टाइम्स (24 सितंबर) के अनुसार मलेशिया के इस्लामी बोर्डिंग स्कूलों में बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं की देशव्यापी जांच के बाद पुलिस ने 355 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से अधिकांश मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवी शामिल हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार जिन इस्लामी मदरसों में बच्चों के यौन शोषण के बारे में व्यापक रूप से जांच की गई है उनका प्रबंधन ग्लोबल इखवान सर्विस एंड बिजनेस (जीआईएसबी) नामक एक इस्लामी संगठन के जिम्मे था। पुलिस महानिदेशक रजारुद्दीन हुसैन ने संवाददाताओं को बताया कि इन इस्लामी मदरसों का संचालन अल-अर्कम संप्रदाय द्वारा किया जा रहा था, जिस पर मलेशिया सरकार ने 1994 में प्रतिबंध लगा दिया था।

सरकार को बच्चों के देशव्यापी यौन शोषण की जानकारी पहली बार दिसंबर 2023 में मिली थी। इसके बाद कई इस्लामी मदरसों पर छापे मारे गए और वहां से यौन शोषण से पीड़ित 400 से अधिक बच्चों को मुक्त किया गया। इस संदर्भ में 171 अध्यापकों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें अधिकांश मदरसों और मस्जिदों का संचालन करने वाले मौलवी शामिल थे। डॉक्टरों द्वारा जांच करने पर इस आरोप की पुष्टि हुई है कि इन स्कूलों में बच्चों का यौन शोषण किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार के निर्देश पर इस्लामी मदरसों के अतिरिक्त घरों में चलाए जा रहे बाल केंद्रों पर भी छापे मारे गए। इसके बाद देशभर के 82 स्थानों पर छापे मारे गए और वहां से यौन शोषण से पीड़ित 186 बच्चों को मुक्त करवाया गया। इसके अतिरिक्त जीआईएसबी के 96 बैंक खातों को जब्त किया गया है, जिनमें लगभग एक लाख 24 हजार डॉलर जमा थे।

इस संस्थान के वेबसाइट पर इसका परिचय एक इस्लामी कारोबारी संस्थान के रूप में दिया गया है, जिसका जाल इंडोनेशिया, फ्रांस और

ब्रिटेन सहित अनेक यूरोपीय देशों में भी फैला हुआ है। प्रारंभ में जीआईएसबी के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नसीरुद्दीन अली ने इन आरोपों का खंडन किया था, लेकिन बाद में उन्होंने यह स्वीकार किया कि ऐसी कुछ घटनाएं हो सकती हैं, जिनमें बच्चों को यौन शोषण का शिकार बनाया गया हो। पुलिस महानिदेशक ने संवाददाताओं को बताया कि इस संस्थान और उससे संबंधित गिरोह द्वारा संचालित इस्लामी मदरसों को मिलने वाले आर्थिक संसाधनों की व्यापक रूप से जांच की जा रही है।

बांग्लादेश में उमड़ रहा है पाकिस्तान प्रेम

अखबार-ए-मशरिक (28 सितंबर) के अनुसार बांग्लादेश में पाकिस्तान के प्रति प्रेम बड़ी तेजी से उमड़ रहा है। बांग्लादेश की आजादी के बाद पहली बार हाल ही में देश की राजधानी ढाका के नेशनल प्रेस क्लब में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी मनाई गई। इस कार्यक्रम के अनेक वक्ताओं ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया और यह मांग की कि मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान के साथ-साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रपिता घोषित किया जाए। उनका तर्क था कि अगर पाकिस्तान न बनता तो बांग्लादेश भी कभी वजूद में नहीं आता। खास बात यह है कि इस समारोह में बांग्लादेश में पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त कामरान धंगल को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। इस समारोह का आयोजन नवाब सलीमुल्लाह एकेडमी की ओर से किया गया था। सलीमुल्लाह ने 1906 में मुस्लिम लीग की नींव रखी थी। आश्चर्य की बात है कि इस समारोह के सभी वक्ताओं ने बांग्ला के बजाय उर्दू में भाषण दिया।

गौरतलब है कि बांग्लादेश भले ही 1971 में पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त हुआ हो, लेकिन

आजाद बांग्लादेश की नींव 1952 में ही रख दी गई थी। तब मोहम्मद अली जिन्ना ने ढ़ाका विश्वविद्यालय के परिसर में यह घोषणा की थी कि पाकिस्तान की एकमात्र सरकारी भाषा उर्दू होगी। जबकि उस समय पाकिस्तान की कुल जनसंख्या में बांग्लाभाषी लोगों का प्रतिनिधित्व 56 प्रतिशत था। वहीं, सिर्फ दस प्रतिशत ही उर्दूभाषी थे। जिन्ना के इस बयान के खिलाफ तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में उग्र विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान में उर्दू के साथ-साथ बांग्ला भाषा को भी मान्यता देने की घोषणा की थी। शेख हसीना के शासन के खात्मे के बाद बांग्लादेश में भारी राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं। देश में जो नया शासन आया है उसके इशारे पर न सिर्फ बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान की प्रतिमाओं को तोड़ा गया है, बल्कि बांग्लादेश में जिन्ना और पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति की नई लहर भी पैदा की जा रही है। बंगाली जनता की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए बाकायदा अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने यह घोषणा की है कि सेना बांग्लादेश की वर्तमान मोहम्मद यूनुस सरकार का समर्थन करती रहेगी। कुछ दिनों पहले न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच बातचीत हुई थी। इसके बाद इन दोनों नेताओं ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह दावा किया कि अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच दोस्ती का नया अध्याय शुरू होगा।

उर्दू टाइम्स (27 सितंबर) के अनुसार बांग्लादेश की नई सरकार ने देश की महिला सैनिकों को यह निर्देश दिया है कि वे हिजाब पहनें। सरकार ने हिजाब को उनकी सैन्य पोशाक में भी शामिल कर दिया है। गौरतलब है कि सन 2000 में महिलाओं को बांग्लादेश की सेना में शामिल करने की घोषणा की गई थी। तब महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बांग्लादेश के सेना मुख्यालय ने हिजाब में इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े के रंग और साइज भी तय कर दिए हैं। बांग्लादेश में महिलाएं अभी भी थलसेना और आर्मर्ड कोर में अधिकारी नहीं बन सकती हैं।

पाकिस्तान में शिया–सुन्नी झड़पों में 46 लोगों की मौत

अवधनामा (28 सितंबर) के अनुसार पाकिस्तान के सीमावर्ती खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शिया-सुन्नी झड़पों ने भयंकर रूप ले लिया है। इन झड़पों में अब तक 46 लोग मारे जा चुके हैं। जबकि 80 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कुर्रम जिला के उपायुक्त जावेद उल्लाह मसूद ने यह स्वीकार किया है कि शिया-सुन्नी जनजातियों के बीच खूनी झड़पों का सिलसिला जारी है। प्रशासन और पुलिस इन झड़पों को रोकने का प्रयास कर रही है। जानकार सूत्रों के अनुसार इन झड़पों में मरने वालों की संख्या सरकारी बयान से काफी अधिक है। इन झड़पों को देखते हुए पाराचिनार-पेशावर मेन रोड और पाकिस्तानी सीमा खारलाची को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान सरकार को यह संदेह है

कि इन झड़पों को अफगानिस्तान में रहने वाले आतंकवादियों द्वारा हवा दी जा रही है।

एतेमाद (21 सितंबर) के अनुसार उत्तरी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के बीच हुई झड़पों में 12 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। जबकि इन झड़पों में छह पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना के लोक संपर्क विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आतंकवादी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में घुसने का प्रयास कर रहे थे, जिसे पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने विफल बना दिया। मारे गए आतंकवादियों के कब्जे से भारी मात्रा में गोला बारूद और आधुनिक हथियार बरामद हुए हैं।

हिंदुस्तान (29 सितंबर) के अनुसार पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने यह दावा किया है कि अफगान सरकार इन आतंकवादियों को हथियार और आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। उन्होंने दावा किया कि 26 सितंबर 2024 को पाकिस्तानी सेना ने उत्तरी वजीरिस्तान जिले में आठ आतंकवादियों को गोली से उड़ा दिया है। उनके कब्जे से जो पहचान पत्र मिले हैं, वे उनके अफगान नागरिक होने की पुष्टि करते हैं। इन आतंकवादियों का संबंध हाफिज गुल बहादुर गुट से था। उनके कब्जे से जो हथियार पाए गए हैं वे भी विदेशी हैं।

अवधनामा (20 सितंबर) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थाई प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने आरोप लगाया है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान विदेशी भूमि से पाकिस्तानी क्षेत्रों पर हमले कर रहा है। हाल ही में उसकी गतिविधियों में भारी वृद्धि हुई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस संगठन के तार अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने विश्व के देशों से आग्रह किया कि वे पाकिस्तान में उभर रहे आतंकवाद के उन्मूलन के लिए पाकिस्तान को सहायता दें।

अफगानिस्तान में दाढ़ी काटने और जींस पहनने पर प्रतिबंध

रोजनामा सहारा (25 सितंबर) के अनुसार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने यह आदेश दिया है कि अब कोई भी अफगान नागरिक न तो अपनी दाढ़ी कटवा सकेगा और न ही जींस पहन सकेगा। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि अफगानिस्तान की वर्तमान सरकार इस्लाम और शरिया कानूनों को मानने वाली सरकार है और वह इन पाबंदियों को सख्ती से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस आदेश में नमाज पढ़ने और रोजा रखने को भी अनिवार्य कर दिया गया है। देश के

सभी नागरिकों को यह चेतावनी दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति इस्लामी जीवन पद्धति को त्यागकर काफिरों के तौर तरीके अपनाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ कार्रवाई का आधार शरिया कानून होगा, जिसमें जुर्माना, कैद और सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने की भी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त इस्लामी शरिया में बलात्कार के आरोपियों को संगसार (पत्थर मार-मार कर मार डालना) करने की भी व्यवस्था है।

जाकिर नाइक पाकिस्तान में

सियासत (30 सितंबर) के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आमंत्रण पर विवादित इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंच गया है। वह 20 दिनों तक पाकिस्तान में रहेगा। इस दौरान वह इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेगा। उसके साथ उसका बेटा फारिक नाइक भी मौजूद है। पाकिस्तान के बहुचर्चित पत्रकार नादिर अली से बातचीत करते हुए जाकिर नाइक ने कहा कि उसके प्रचार के कारण भारत में भारी संख्या में गैर-मुसलमान इस्लाम स्वीकार कर रहे थे और उसके इस अभियान से वहां की भाजपा सरकार डर गई थी, इसलिए उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाकर मुकदमे दर्ज किए गए। उसने दावा किया कि उसके कार्यक्रमों में भाग लेने वाले 50 प्रतिशत लोग गैर-मुस्लिम होते थे और उसके दावती व तब्लीगी मिशन के कारण कम-से-कम 25 हजार हिंदुओं ने इस्लाम स्वीकार किया। उसने कहा कि मैं भारत लौटना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर है कि वहां की मोदी सरकार मुझे गिरफ्तार कर लेगी।

जाकिर नाइक ने कहा कि "इस्लाम का प्रचार करना हर मुसलमान का कर्तव्य है। कयामत के वक्त अल्लाह ताला हर मुसलमान से यह पूछेगा कि उसने कितने काफिरों को मुसलमान बनाया और तब्लीगी दावत के लिए कितने आयोजन किए?" उसने यह भी दावा किया कि गैर-मुसलमानों को इस्लाम में लाना हर मुसलमान का बुनियादी इस्लामी कर्तव्य है। किसी भी सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि वह काफी दिनों से पाकिस्तान आना चाहता था, लेकिन वह इस डर से पाकिस्तान नहीं आया कि भारत सरकार उसे पाकिस्तानी एजेंट बताकर उस पर और मुकदमे दर्ज कर देगी। यही कारण है कि वह मक्का से मलेशिया चला गया। जाकिर ने कहा कि वह उन देशों में इस्लाम का प्रचार करने में अधिक रुचि रखता है, जहां की अधिकांश आबादी गैर-मुस्लिम है। उसने कहा कि मैं विशेष रूप से बांग्लादेश और नेपाल जाना चाहता हूं ताकि वहां पर इस्लाम का प्रचार-प्रसार कर सकूं।

जाकिर नाइक ने दावा किया कि "अधिकांश भारतीय हिंदू इस्लाम स्वीकार करने की तीव्र इच्छा रखते हैं, क्योंकि इस्लाम में उन्हें जात-पात के भेदभाव से मुक्ति मिलती है। इस्लाम में जो समता है उसके कारण प्रारंभ से ही हिंदू

समाज के लोग इस्लाम स्वीकार करते आ रहे हैं। यह आरोप गलत है कि भारत में इस्लाम तलवार के बल पर या मुस्लिम शासकों के दबाव पर फैला।" उसने दावा किया कि मलेशिया की सरकार की ओर से उसे हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं और वह वहां पर गैर-मुसलमानों को इस्लाम की दावत देने में जुटा हुआ है। जाकिर नाइक का बेटा फारिक नाइक ने कहा कि मोदी की हिंदूवादी सरकार उसके पिता के खिलाफ इसलिए है, क्योंकि उसे यह डर है कि अगर उसके पिता को भारत में इस्लाम का प्रचार करने की छूट दी गई तो लाखों हिंदू इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। उसने कहा कि हम किसी से डरने वाले नहीं है। दावत-ए-इस्लाम हमारा पवित्र इस्लामी कर्तव्य है और हम इस्लाम के प्रचार व प्रसार के लिए कटिबद्ध हैं।

ईरान द्वारा 40 लाख अफगान नागरिकों को निष्कासित करने का फैसला

रोजनामा सहारा (26 सितंबर) के अनुसार ईरान सरकार ने यह घोषणा की है कि उसके देश में 40 लाख से अधिक अफगान नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं। इन लोगों को वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। दूसरी ओर, अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता ने यह पुष्टि की है कि हर रोज औसतन तीन हजार अफगान नागरिक ईरान से वापस अफगानिस्तान आ रहे हैं। सरकारी प्रवक्ता अब्दुल गनी काजीजादा ने आरोप लगाया है कि ईरान सरकार अफगान मूल के उनलोगों को भी जबरन अपने देश से निकाल रही है, जो ईरान में ही पैदा हुए थे और वहां के विधिवत नागरिक हैं। उन्होंने दावा किया कि ईरान सरकार की ओर से अफगान मूल के नागरिकों को धमकी दी गई है कि वे एक सप्ताह के अंदर अपने देश वापस चले जाएं, वरना उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

काजीजादा ने आरोप लगाया कि ईरान सरकार की नीति अफगान विरोधी है। उसने अपने देश के सभी नागरिकों को यह धमकी दी है कि अगर उन्होंने किसी भी अफगान नागरिक को किराए पर मकान दिया या उन्हें नौकरी दी तो दोषी व्यक्ति को तीन साल कैद की सजा दी जाएगी। ईरान पुलिस और सेना चुन-चुनकर अफगान नागरिकों को हिरासत में लेने के बाद उन्हें नजरबंदी शिविरों में भेज रही है। काजीजादा ने यह भी आरोप लगाया कि ईरानी सैनिक अफगान नागरिकों के पासपोर्ट या वीजा फाड़ देते हैं ताकि वे यह साबित कर सकें कि ये अफगान नागरिक अवैध रूप से ईरान में रह रहे थे। ईरान की सरकारी संवाद समिति 'आईआरएनए' के अनुसार ईरान में अफगान शरणार्थियों की संख्या 45 लाख तक पहुंच चुकी है। ये शरणार्थी अवैध रूप से ईरान में दाखिल हुए थे, इसलिए इनको देश से निष्कासित करना बेहद जरूरी था।

इजरायल द्वारा हमास और हिजबुल्लाह के शीर्ष नेतृत्व का खात्मा

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (29 सितंबर) के अनुसार ईरान समर्थक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का प्रमुख सैयद हसन नसरल्लाह इजरायली हमले में मारा गया है। इजरायल के सैन्य प्रवक्ता ने सबसे पहले उसके मारे जाने की सूचना दी थी। बाद में हिजबुल्लाह के प्रवक्ता ने भी उसकी मौत की पुष्टि की। बताया जाता है कि जब नसरल्लाह मारा गया तो वह लेबनान की राजधानी बेरूत में स्थित अपने भूमिगत कार्यालय में मौजूद था। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंटों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर इजरायली वायुसेना ने उसके कार्यालय को अपना निशाना बनाया। इजरायली वायुसेना ने इस हमले में 80 टन वजनी दो दर्जन बमों का इस्तेमाल किया। ये बम बंकर बस्टर कहलाते हैं, जो भूमिगत ठिकानों और बंकरों में छिपे हुए लोगों को निशाना बनाते हैं। हसन नसरल्लाह के साथ उसकी बेटी जैनब भी मारी गई है।

हिंदुस्तान (29 सितंबर) के अनुसार इजरायल अब तक हिजबुल्लाह के 16 शीर्ष कमांडरों को मौत के घाट उतार चुका है। सबसे पहले 30 जुलाई को फुआद शुक्र मारा गया था। वह इजरायल पर हिजबुल्लाह के हमलों का मुख्य संचालक था। फुआद हिजबुल्लाह का सबसे वरिष्ठ कमांडर था और उसे हसन नसरल्लाह का मुख्य सहयोगी माना जाता था। अमेरिका ने 2017 में फवाद शुक्र की सूचना देने वालों को 50 हजार डॉलर ईनाम देने की घोषणा की थी। 20 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह के रादवान यूनिट का कमांडर इब्राहिम अकील मारा गया। उसके साथ हिजबुल्लाह के 15 अन्य कमांडर भी इजरायली हमले में मारे गए। हिजबुल्लाह सूत्रों के अनुसार इब्राहिम अकील इस संगठन का दूसरा सबसे वरिष्ठ कमांडर था। वह हिजबुल्लाह की जिहाद काउंसिल का वरिष्ठ सदस्य था। 1983 में अकील के इशारे पर बेरूत स्थित अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया था, जिसमें 63 लोग मारे गए थे। 24 सितंबर को एक अन्य इजरायली हवाई हमले में इब्राहिम मुहम्मद कबीसी मारा गया। वह हिजबुल्लाह के गाइडेड मिसाइल यूनिट का

कमांडर था। कबीसी 1982 में हिजबुल्लाह में शामिल हुआ था। 26 सितंबर को एक अन्य इजरायली हमले में मोहम्मद सुरूर मारा गया। वह पिछले एक दशक से हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट का प्रमुख था। इसके अतिरिक्त इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के दो अन्य वरिष्ठ कमांडर विसाम अल-तवील और मोहम्मद नासिर मारे गए हैं।

लेबनान में हिजबुल्लाह के निर्देशक तालेब अब्दुल्ला को भी इजरायल ने मार गिराया है। वह दक्षिणी लेबनान फ्रंट का प्रमुख था। इसके अतिरिक्त हिजबुल्लाह के रादवान फोर्स का प्रमुख अहमद वहाबी भी इजरायली हमले में मारा गया है। तेहरान में ईरानी सैन्य प्रवक्ता ने इस खबर की पुष्टि की है कि पासदारान-ए-इंकलाब (आईआरजीसी) के वरिष्ठ कमांडर अब्बास निलफोरुशन भी इजरायली हमले में मारे गए हैं। ईरानी रक्षा मंत्रालय ने एक इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के साउदर्न फ्रंट के प्रमुख अली कराकी के मारे जाने की भी पुष्टि की है। उसके साथ-साथ हिजबुल्लाह के एक दर्जन से अधिक कमांडर भी मारे गए हैं। हिजबुल्लाह के प्रवक्ता ने कहा है कि इजरायली हमलों में लगभग 1200 लेबनानी नागरिक मारे गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

एतेमाद (29 सितंबर) के अनुसार हसन नसरल्लाह का जन्म 1960 में पूर्वी बेरूत के एक गरीब शिया परिवार में हुआ था। उसे लेबनान की सबसे ताकतवर हस्ती माना जाता था। 15 वर्ष की उम्र में वह शिया मिलिशिया संगठन इस्लामिक अमल में शामिल हो गया था। उसकी शिक्षा-दीक्षा इराक के नगर नजफ में हुई थी। नजफ में हजरत अली की दरगाह है। 1992 में इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह का तत्कालीन प्रमुख सैयद अब्बास अल-मुसावी मारा गया। इसके बाद नसरल्लाह को हिजबुल्लाह का प्रमुख बनाया गया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया। इसके बाद हिजबुल्लाह ने भी इजरायली सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। नसरल्लाह ने घोषणा की कि जब तक इजरायल गाजा में अपने हमले नहीं रोकेगा, हिजबुल्लाह इजरायल को अपने हमलों का निशाना बनाता रहेगा। नसरल्लाह की मौत पर एक दर्जन से अधिक इस्लामी देशों ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इनमें इराक, ईरान, सीरिया, पाकिस्तान आदि शामिल हैं।

एक अन्य समाचार के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा है कि इजरायल के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत हिजबुल्लाह और हमास को खत्म नहीं कर सकती।

उर्दू टाइम्स (30 सितंबर) के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी दी थी कि इजरायल की पहुंच से कोई भी दूर नहीं है। इस धमकी के बाद हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। नसरल्लाह किसी भी स्थान पर एक दिन से अधिक नहीं ठहरता था। वह हिजबुल्लाह के मुख्यालय में आयोजित एक बैठक में भाग लेने के लिए बेरूत गया था। बैठक खत्म होते ही वह वहां से किसी अन्य स्थान पर जाने ही वाला था कि मोसाद ने उसके ठिकाने का सुराग लगा लिया।

इसके बाद इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने कुछ ही मिनटों में नसरल्लाह को अपना निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के प्रवक्ता ने कहा है कि हसन नसरल्लाह के शरीर पर कोई घाव नहीं पाया है। संभवतः उसकी मौत धमाके से हुई है।

उल्लेखनीय है कि इजरायल इससे पहले ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के प्रमुख इस्माइल हानियेह की हत्या कर चुका है। हानियेह की हत्या तब की गई, जब वह एक अति सुरक्षित स्टेट गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। वह ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान गया था। इससे पहले 2 जनवरी 2024 को इजरायल ने हमास के उप प्रमुख और अल-कस्साम ब्रिगेड के संस्थापक सालेह अल अरौरी को एक ड्रोन हमले में मार गिराया था। इसके बाद 13 जुलाई को इजरायल ने एक अन्य हवाई हमले में हमास के बड़े नेता मोहम्मद दीफ की हत्या कर दी।

हिंदुस्तान (30 सितंबर) के अनुसार इजरायल ने हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ कमांडर नबील कौक को भी मार गिराया है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (30 सितंबर) के अनुसार इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद अपने दुश्मनों को अनेक तरीके से निशाना बनाती रही है। मोसाद का गठन 1949 में किया गया था। मोसाद ने नाजी जर्मनी में लाखों यहूदियों के हत्यारे लेफ्टिनेंट कर्नल एडोल्फ आइशमन का सुराग 25 वर्ष बाद लगाया था और उसे अर्जेंटीना से इजरायल लाया गया था। इसके बाद उसे फांसी पर लटका दिया गया था। 1970 में मोसाद ने सद्दाम हुसैन की हत्या का प्रयास किया था। फिलिस्तीनी कमांडर वादी हद्दाद की हत्या मोसाद ने की थी। 1972 में जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित ओलंपिक गेम्स के दौरान फिलिस्तीनियों ने 11 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी। बदले में मोसाद ने पेरिस में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि महमूद हमशारी की हत्या टेलफोन में धमाका करके कर दी। 1979 में नॉर्वे में मोसाद के एजेंटों ने यासिर अराफात के सुरक्षा प्रमुख अली हसन सलामेह को मौत के घाट उतार दिया। 2010 में मोसाद के एजेंटों ने हमास के उप प्रमुख महमूद अल-मबहौह की हत्या दुबई के एक होटल में कर दी। 2020 में मोसाद के एजेंटों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पलीता लगाने के लिए ईरान के पांच प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर दी थी। इसके बाद ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसेन फखरीजादेह को भी मार दिया गया।

हाशिम सफीद्दीन हिजबुल्लाह का नया प्रमुख

कौमी तंजीम (19 सितंबर) के अनुसार हाशिम सफीद्दीन को हिजबुल्लाह का नया प्रमुख घोषित किया गया है। वह मृतक हसन नसरल्लाह की मौसी का बेटा है। उसकी शक्ल-सूरत हसन नसरल्लाह से काफी मिलती है। 1994 में ईरान के शिया केंद्र कोम के मदरसे से उच्च धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद सफीद्दीन को हिजबुल्लाह की गवर्निंग बॉडी में शामिल किया गया था। अभी

तक वह हिजबुल्लाह के वित्तीय मामलों को देखता था। इसके अतिरिक्त उसके जिम्मे राजनीतिक विभाग भी है। उसे ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के विश्वस्त लोगों में गिना जाता है। ईरान के साथ उसके अब भी नजदीकी संपर्क हैं। उसके बेटे का निकाह ईरानी मिलिशिया पासदारान-ए-इंकलाब (आईआरजीसी) के विदेश विभाग के संचालक कासिम सुलेमानी की बेटी से हुआ था। अमेरिका ने 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी थी। हाशिम सफीद्दीन हिजबुल्लाह की संचालन कमेटी के सात महत्त्वपूर्ण सदस्यों में शामिल है। अमेरिका ने उसे मई 2017 में आतंकवादी सूची में शामिल किया था और उसकी सूचना देने वालों को एक करोड़ डॉलर का ईनाम देने की घोषणा की थी। उसने एक दशक तक नसरल्लाह के सहायक के रूप में काम किया है। इससे पहले उसे 2008 में भी हिजबुल्लाह का अस्थाई प्रमुख नियुक्त किया गया था। हाशिम सफीद्दीन आम तौर पर सार्वजनिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता है और वह गुप्त रूप से हिजबुल्लाह के लिए काम करता है।

हिजबुल्लाह को ईरान के आईआरजीसी के मॉडल पर बनाया गया था। इसकी नींव 1982 में लेबनान के गृह युद्ध के दौरान रखी गई थी। हाल ही में सफीद्दीन ने कहा था कि इजरायल के खिलाफ उसका संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हिजबुल्लाह का एक भी लड़ाका जिंदा है। अगर हिजबुल्लाह का एक व्यक्ति मरेगा तो दूसरा व्यक्ति फौरन हिजबुल्लाह का परचम थाम लेगा और नए संकल्प के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। सफीद्दीन के पारिवारिक जीवन और निवास के बारे में रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है, क्योंकि हिजबुल्लाह और ईरान के नेताओं को यह डर है कि इजरायल की गुप्तचर एजेंसी मोसाद उसे अगला निशाना बना सकती है। हाल ही में उसे आईआरजीसी का रक्षा कवच भी प्रदान किया गया है।

पेजर और वॉकी-टॉकी में हुए धमाकों से दहला लेबनान

औरंगाबाद टाइम्स (19 सितंबर) के अनुसार इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद द्वारा लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों द्वारा आपस में संदेशों के आदान-प्रदान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेजरों में एक साथ धमाका किया गया। इन धमाकों में कम-से-कम 25 लोग मारे गए और लगभग पांच हजार लोग घायल हो गए। लेबनान स्थित ईरानी राजदूत मोजतबा अमानी भी पेजर धमाके के शिकार हुए हैं और उनकी दोनों आंखों की रोशनी खत्म हो गई है। लेबनान के विभिन्न क्षेत्रों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों की जेबों में रखे पेजर बमों की तरह फटने लगे। हिजबुल्लाह के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। बताया जाता है कि पेजरों में धमाके की साजिश इजरायली

खुफिया एजेंसी मोसाद ने रची थी। कहा जाता है कि मोसाद ने इस हमले की तैयारी चार साल पहले ही शुरू कर दी थी। अभी तक ईरानी गुप्तचर तंत्र इस बात का पता नहीं लगा सका है कि इजरायली वैज्ञानिकों ने इन पेजरों में किस तरह से विस्फोटक पदार्थ फिट किए थे।

अभी लेबनान पेजर धमाकों से उबर भी नहीं पाया था कि हिजबुल्लाह के सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सैकड़ों वॉकी-टॉकी भी बमों की तरह फटने लगे। इन धमाकों में लगभग दो हजार लोग घायल हो गए और 45 मारे गए। लेबनानी सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि हिजबुल्लाह ने इस वर्ष की शुरुआत में लगभग पांच हजार पेजर ताइवान की एक एजेंसी से खरीदे थे। जबकि वॉकी-टॉकी ऑस्ट्रिया की एक एजेंसी से खरीदे गए। खास बात यह है कि ताइवान की एजेंसी ने यह दावा किया है कि ये पेजर उसने सप्लाई नहीं किए थे और वह इनका उत्पादन चार साल पहले ही बंद कर चुकी है। यही स्थिति वॉकी-टॉकी की भी है। कोई भी विदेशी कंपनी यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि जिन वॉकी-टॉकी उपकरणों में धमाका हुआ है उन्हें उनकी कंपनी द्वारा सप्लाई किया गया था। वहीं, लेबनान की सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि ये पेजर सीधे लेबनान नहीं आए, क्योंकि लेबनान में इस तरह के उपकरण मंगवाने पर पूर्ण प्रतिबंध है।

अवधनामा (19 सितंबर) के अनुसार हिजबुल्लाह ने घोषणा की है कि इजरायल को इस हरकत का ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इन धमाकों के बाद पूरे लेबनान में इमरजेंसी लागू कर दी गई है और अस्पतालों में दो हजार से अधिक घायलों को भर्ती किया गया है। गौरतलब है कि हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने इस साल के प्रारंभ में अपने लड़ाकों को यह निर्देश दिया था कि वे मोबाइल का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इसके जरिए इजरायली खुफिया एजेंसियां उनके लोकेशन का पता लगा सकती हैं।

उर्दू टाइम्स (20 सितंबर) के अनुसार ईरानी कमांडर मोहसेन राफिगदूस्त ने कहा है कि ईरान सरकार ने अपने सभी उच्चाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वे आपसी बातचीत के लिए मोबाइल का इस्तेमाल न करें। इस संबंध में सरकार ने एक उच्चस्तरीय कमेटी का भी गठन किया है, जो यह जांच करेगी कि ईरान के अधिकारियों के पास जो मोबाइल हैं, वे किस हद तक सुरक्षित हैं। इस कमेटी में गुप्तचर विभाग के उच्चाधिकारी शामिल हैं।

अवधनामा (20 सितंबर) के अनुसार हिजबुल्लाह ने यह स्वीकार किया है कि पेजरों और वॉकी-टॉकी में धमाका होना सुरक्षा एजेंसियों की बहुत बड़ी चूक है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार जिन कंपनियों ने हिजबुल्लाह को पेजर व वॉक-टॉकी सप्लाई किए थे उन्हें एक दशक पहले इजरायली एजेंटों ने विदेशों में स्थापित की थी। उन्होंने अपनी पहचान को गुप्त रखा था। ताइवान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां इस संदर्भ में उच्चस्तरीय जांच कर रही हैं।

रोजनामा सहारा (20 सितंबर) के अनुसार जिस कंपनी ने हिजबुल्लाह को पेजर सप्लाई किए

थे उसकी प्रमुख इटली की एक 49 वर्षीय महिला है। इस कंपनी की स्थापना 2022 में की गई थी और इसका मुख्यालय हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में है। गुप्तचर एजेंसियों ने इस संदर्भ में केरल के रहने वाले एक भारतीय मूल के व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

रोजनामा सहारा (27 सितंबर) के अनुसार ताइवान सरकार ने लेबनान में हुए पेजर धमाकों के सिलसिले में पूछताछ शुरू कर दी है। इस संबंध में अभी तक चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनका संबंध ताइवान स्थित गोल्ड अपोलो नामक कंपनी से है। कहा जाता है कि इसी कंपनी ने हिजबुल्लाह को पेजर सप्लाई किए थे।

रोजनामा सहारा (28 सितंबर) के अनुसार नॉर्वे में भी इन धमाकों से संबंधित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने इस व्यक्ति के संबंध में अत्यधिक जानकारी देने से इंकार कर दिया है। बताया जाता है कि इस व्यक्ति का संबंध बुल्गारिया से है। यह संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि जिस कंपनी ने ये पेजर सप्लाई किए थे उसके तार नॉर्वे की एक कंपनी नॉर्टा ग्लोबल से जुड़े हुए हैं।

एतेमाद (25 सितंबर) ने अपने संपादकीय में पेजरों और वॉकी-टॉकी में हुए धमाकों को एक खतरनाक संकेत बताया है। समाचारपत्र ने कहा है कि इन हमलों से यह साबित हो गया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अब सुरक्षित नहीं है। भारत में जिस तरह से विदेशों में बने मोबाइलों का इस्तेमाल हो रहा है उसकी सुरक्षा के लिए भी उच्चस्तरीय जांच करवाने की जरूरत है।

मुंबई उर्दू न्यूज (21 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इजरायल ने लेबनान में पेजरों में हमला करके दुनिया को चौंका दिया है। सवाल यह उठता है कि क्या इन हमलों से हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है? ऐसा दावा करना सरासर गलत होगा। दुनिया के अधिकांश देशों में पेजर का इस्तेमाल खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं, जहां पर इंटरनेट टावर मौजूद नहीं हैं। वहां पर मैसेज भेजने के लिए पेजरों का इस्तेमाल किया जाता है। हिजबुल्लाह के लड़ाके सुरक्षित समझकर इसका इस्तेमाल कर रहे थे। अब यह साफ हो गया है कि इन्हें कोई भी हैक कर सकता है। मजेदार बात यह है कि अभी तक गुप्तचर एजेंसियां यह पता नहीं लगा पाई हैं कि किस कंपनी ने इन पेजरों की सप्लाई की थी।

उर्दू टाइम्स (19 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इजरायल ने जिस तरह से पेजरों में धमाका करके हिजबुल्लाह के लड़ाकों की सामूहिक हत्या करने का प्रयास किया है वह एक खतरनाक संकेत है। पहले यह दावा किया गया था कि ये पेजर ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन अब इस कंपनी ने कहा है कि वह इनका उत्पादन कई वर्ष पहले ही बंद कर चुकी है। हिजबुल्लाह का दावा है कि यह हमला इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने किया है। हालांकि, इजरायल ने यह हथकंडा लेबनान की जनता में दहशत फैलाने के लिए अपनाया है।

अमेरिका द्वारा इजरायल को पौने नौ अरब डॉलर की सहायता

इंकलाब (28 सितंबर) के अनुसार अमेरिका ने इजरायल को पौने नौ अरब डॉलर की नई सैन्य सहायता उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। इसमें साढ़े तीन अरब डॉलर के हथियार भी शामिल हैं, जो इजरायल को पहले ही सप्लाई किए जा चुके हैं। जबकि इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को और अधिक कारगर बनाने के लिए सवा पांच अरब डॉलर की धनराशि दी गई है।

एतेमाद (20 सितंबर) के अनुसार जर्मन संवाद समिति 'डीपीए' ने दावा किया है कि जर्मनी की सरकार ने इस बात का खंडन किया है कि जर्मनी ने इजरायल को हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। जर्मन रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इजरायल को हथियारों का निर्यात जारी रहेगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों ब्रिटिश संवाद समिति 'रॉयटर्स' ने यह खबर दी थी कि राजनीतिक दबाव के कारण जर्मन सरकार ने इजरायल को हथियारों की सप्लाई पर रोक लगा दी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जर्मनी ने पिछले साल इजरायल को 363 मिलियन डॉलर के सैन्य उपकरण निर्यात किए थे, जो 2022 की तुलना में दस गुना अधिक था। वहीं, इस वर्ष के शुरुआती आठ महीनों में इजरायल को केवल 14.5 मिलियन यूरो के हथियार बेचने की मंजूरी दी गई है।

इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देशों का मोर्चा

अवधनामा (20 सितंबर) के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अंतरराष्ट्रीय इस्लामिक एकता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विश्वभर के मुस्लिम देशों से अपील की है कि वे इजरायल के इस्लाम विरोधी एजेंडे को विफल बनाने के लिए एकजुट हो जाएं ताकि मुट्ठी भर यहूदी गाजा में मुस्लिम महिलाओं और बच्चों के नरसंहार करने की हिम्मत न कर सकें। उन्होंने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि "अल्लाह ने मुसलमानों से अपील की है कि वे इस्लाम की रक्षा के लिए एकजुट हो जाएं। कुरान में मुसलमानों को विभाजित करने की साजिश को सबसे बड़ा गुनाह करार दिया गया है।" उन्होंने कहा कि 20-30 लाख यहूदी गाजा में हजारों निर्दोष मुसलमानों का कत्ल कर चुके हैं। यही नहीं वे मस्जिदों और अस्पतालों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। यहूदियों को इस तरह की हरकत करने की हिम्मत इसलिए हो रही है, क्योंकि मुसलमानों में एकता नहीं है और वे छोटी-छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पेजेश्कियान ने कहा कि "इस्लाम, कुरान और रसूल की रक्षा के लिए यह जरूरी है कि विश्वभर के मुसलमान एकजुट होकर नया एक्शन प्लान तैयार करें। वे अपने सभी आपसी समस्याओं और विवादों को भूलकर इस्लाम व उम्माह के दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए एकजुट हो जाएं।" इस अवसर पर ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता सैयद अली खामेनेई ने भी अंतरराष्ट्रीय इस्लामिक एकता सम्मेलन के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि यहूदियों ने यूरोपीय शक्तियों के

सहयोग से फिलिस्तीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। वे अब जॉर्डन, लेबनान और सीरिया जैसे मुस्लिम देशों को भी हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि सभी मुस्लिम देश एकजुट हों। उन्होंने कहा कि इजरायल जैसे कैंसर का सफाया करें और अमेरिका जैसे इस्लाम दुश्मन देश को मिट्टी में मिला दें।

उर्दू टाइम्स (30 सितंबर) के अनुसार ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने घोषणा की है कि ईरान इजरायल के खिलाफ संघर्षशील विभिन्न गुटों को हर तरह का समर्थन और सहायता उपलब्ध कराता रहेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अमेरिका इजरायल को हथियारों के साथ-साथ आर्थिक सहायता दे रहा है उससे इस क्षेत्र में शांति स्थापना की कोई संभावना नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह या हमास के सेनानियों की हत्या के कारण हमारे हौसले टूटने वाले नहीं है। हमारा संघर्ष आखिरी दम तक जारी रहेगा। गालिबफ ने विश्व के मुस्लिम देशों से अपील की कि वे आपसी मतभेदों को भुलाकर इजरायल का सामना करने के लिए एकजुट हो जाएं।

उर्दू टाइम्स (25 सितंबर) के अनुसार हिजबुललाह के उप प्रमुख शेख नईम कासिम ने कहा है कि हम अभी यह सार्वजनिक घोषणा नहीं करेंगे कि इजरायल के खिलाफ हमारा अगला कदम क्या होगा। हम इजरायल से हर कीमत पर अपने 'शहीदों' का बदला लेकर रहेंगे। नईम ने कहा कि गाजा और लेबनान के लिए हमारा समर्थन जारी रहेगा। इजरायल की धमकियों से हिजबुल्लाह दबने वाला नहीं है। हम आखिरी आदमी तक इजरायल के खिलाफ संघर्ष को जारी रखेंगे और इजरायल को अब खतरनाक नतीजे भुगतने पड़ेंगे, जिसे यहूदी कई नस्लों तक याद रखेंगे। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वे आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट हो जाएं और इजरायल के नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिला दें।

एतेमाद (24 सितंबर) के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराघची ने कहा है कि ईरान इजरायली हरकतों पर गहरी नजर रखे हुए है

परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि आज मध्य पूर्व एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में युद्ध भड़के। यह जरूरी है कि विश्व के देश संभावित युद्ध को रोकने के लिए अभी से प्रयास करें। अगर हालात नियंत्रण से बाहर हो गए तो विश्वयुद्ध को रोकना संभव नहीं होगा। रूसी विदेश मंत्री ने लेबनान पर इजरायल के अंधाधुंध हमलों की निंदा करते हुए कहा कि इन हमलों का निशाना आम नागरिक बन रहे हैं और 40 हजार से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस नरसंहार को रोकने के लिए विश्व के देशों को एकजुट होकर कोई ठोस प्रयास करना चाहिए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि पिछले एक साल से इजरायल ने फिलिस्तीन में युद्ध छेड़ रखा है और इस युद्ध का विस्तार भी हो रहा है। ऐसे में इस युद्ध को रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए और इस क्षेत्र में दो स्वतंत्र राज्य स्थापित किए जाने चाहिए। चीन मध्य पूर्व में शांति और विकास चाहता है।

और हम इजरायल को मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि इस पूरे क्षेत्र के हालात दिन-प्रतिदिन खतरनाक होते जा रहे हैं। विश्व को इजरायल के आक्रामक इरादों को रोकने के लिए संयुक्त रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर दुख प्रकट किया है कि अभी तक विश्व के अधिकांश देश इजरायल की आक्रामक कार्रवाईयों को मूकदर्शक बन कर देख रहे हैं। यह विश्व शांति के लिए खतरा है।

औरंगाबाद टाइम्स (30 सितंबर) के अनुसार रूस के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा

माली के सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पर आतंकी हमला

इंकलाब (21 सितंबर) के अनुसार इस्लामी आतंकी संगठन अलकायदा द्वारा अफ्रीका के इस्लामी देश माली की राजधानी बामाको में सैन्य पुलिस प्रशिक्षण शिविर और हवाई अड्डे पर किए गए हमले में 70 लोग मारे गए हैं और 250 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस हमले के बाद हमलावर प्रशिक्षण केंद्र से काफी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी लूटकर ले गए हैं। इस हमले की जिम्मेवारी जमात नुसरत अल-इस्लाम वल-मुस्लिमीन (जेएनआईएम) नामक एक इस्लामी आतंकी संगठन ने ली है। यह संगठन अलकायदा का स्थानीय विंग होने का दावा करता है। अलकायदा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस हमले के वीडियो वायरल किए हैं, जिनमें आतंकवादियों को एक हवाई जहाज को तबाह करते और मारे गए सैनिकों के शवों पर नाचते हुए दिखाया गया है। यह हमला माली, नाइजीरिया और बुर्किना फासो की सीमा पर स्थित एक सैन्य प्रशिक्षण एकेडमी में हुआ है। माली में इन दिनों सैनिक तानाशाही है, जिसका विरोध इस्लामी आतंकवादी कर रहे हैं। पिछले दो सालों से इस देश में गृहयुद्ध चल रहा है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

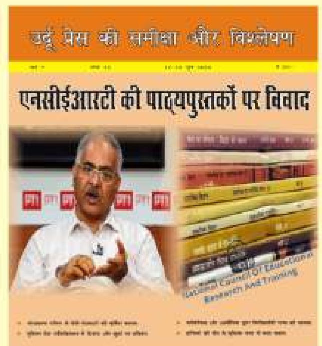

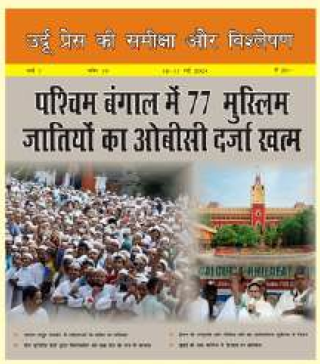

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in